



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 9 अप्रैल, 1988/20 चैत्र, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 4th April, 1988

No. 1-21/88-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly 1973. The Himachal Pradesh Regist-

ration of Tourist Trade Bill, 1988 (Bill, No. 5 of 1988) having been introduced on the 4th April, 1988, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary.

1988 का विधेयक संख्यांक-5

हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने और उनसे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और उससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. (1) यह अधिनियम होटल, पर्यटक विश्राम-गृह, डाक बंगला, सराय, धर्मशाला, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित या चलाए गए किसी संस्थान या परिसर को लागू नहीं होगा ।

छूट ।

(2) राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के समस्त या उनमें से कोई उपबन्ध, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करे, साधारणतया निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(i) पूर्त स्वरूप के लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर का कोई वर्ग;

(ii) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए लोक न्यास द्वारा धारित और नाममात्र किराए पर दिए गए परिसर;

(iii) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए लोक न्यास द्वारा धारित और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित परिसर ।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह भी निदेश दे सकेगी कि ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अध्याय-3 के सभी या उनमें से कोई उपबन्ध ऐसे होटलों या संस्थानों, या होटलों अथवा संस्थानों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “काली सूची” से होटल चलाने वालों, यात्रा एजेंटों, गाइडों तथा भ्रमण एजेंटों के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन काली सूची में डाले जा चुके हैं, रखी गई तथा प्रदर्शित सूची अभिप्रेत है;
 - (ख) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र” से इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;
 - (ग) “व्यवहारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटन क्षेत्र में किसी अधिसूचित वस्तु के विक्रय का, चाहे थोक में या परचून में, कारबार कर रहा हो, और इसमें अन्तर्गत उसकी और से कारबार चला रहा उसका एजेंट या कर्मचारी है;
 - (घ) “भ्रमण एजेंट” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटक/पर्यटकों के लिए भ्रमण/पर्यटन या पिकनिक की व्यवस्था करने में लगा हुआ है या अपने आपको उसमें लगा रहा हो;
 - (ङ) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
 - (च) “गाइड” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटकों के लिए वैतनिक गाइड के रूप में लगा हुआ है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक गाइड के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ऐसी अर्हताएं न रखता हो जो इस निमित्त विहित की जाएं:

परन्तु यह और कि किन्हीं विहित अर्हताओं के होते हुए भी, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, गाइड के रूप में कार्य कर रहे थे, वे स्वयमेव ऐसे गाइड के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे;

- (छ) “होटल” से गृह-नौका, रेस्तरां, मधुशाला या टेंट को शामिल करके, कोई परिसर या परिसरों का भाग अभिप्रेत है जहां खान-पान सहित या रहित आवास या किसी प्रकार के खान-पान या मादक पेय की आर्थिक प्रतिफल के रूप में व्यवस्था की जाती हो और ऐसे परिसर इसमें अन्तर्गत हैं जो मौसम (सीजन) के दौरान किराए पर दिए जाते हैं;
- (ज) “होटल चलाने वाला” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी होटल का स्वामी है या स्वत्वधारी के रूप में होटल चलाता है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो स्वत्वधारी की और से होटल में कार्य की व्यवस्था कर रहा हो; या
- (झ) “स्थानीय प्राधिकरण” से अपनी-अपनी अधिकारिता में, उपायुक्त, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, पंचायत और लोक न्याय अभिप्रेत है;
- (ण) “अनाचार” के अन्तर्गत है छल, दलाली, प्रतिरूपण, दुकानदारी करने के लिए, या ठहरने या यात्रा के प्रबन्ध में बाधा, लेबल पर प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य या इस अधिनियम के अधीन नियत से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, प्रत्येक वस्तु पर मूल्य लेबल प्रदर्शित करने में विकलता, किराए की सूची प्रदर्शित करने में विकलता, केशमेमों देने में विकलता, अनुबद्ध श्रद्धा के भीतर तथा समस्त निबन्धनों के अनुसार आदेश के निष्पादन में जानबूझ कर विकलता और उपलब्ध होने पर पर्यटकों को वास सुविधा की व्यवस्था करने में विकलता या पर्यटकों से भिन्न व्यक्तियों को मौसम (सीजन) के दौरान, दैनिक/मासिक किराए पर वास-सुविधा की व्यवस्था करना;

स्पष्टीकरण-I

इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "लेबल मूल्य" (अधिसूचित वस्तु पर प्रदर्शित लेबल मूल्य) ऐसा युक्तियुक्त मूल्य होगा जो विहित प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए ;

स्पष्टीकरण-II

"दलाली" पद से दुकानदारी, वास-सुविधा, परिवहन, सैर-सपाटे के लिए अवपीड़ित करना या किसी विशेष परिसर, व्यक्ति, स्थापना, व्यवहारी, निर्माता या व्यक्तिगत फायदे के प्रतिफल से पर्यटन सम्बन्धी किसी अन्य सेवा के लिए परेशान करना, अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचित वस्तु" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचित कोई वस्तु अभिप्रेत है, और विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के लिए विभिन्न वस्तुएं अधिसूचित की जा सकेंगी ;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "विहित प्राधिकारी" से सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न प्राधिकारी अधिसूचित किए जा सकेंगे ;

(ण) "मौसम" (सीज़न) से 16 सितम्बर से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है और वर्ष की शेष अवधि "मन्दी का मौसम" होगी ;

(त) "विनिर्दिष्ट वास-सुविधा", चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञातव्य हो, से होटल के सम्बन्ध में अन्य कमरों में प्राप्य वास-सुविधा से भिन्न वास-सुविधा अभिप्रेत है जो होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों को दी जाती है और ऐसे वर्ग को है जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ;

(थ) "पर्यटन क्षेत्र" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा राजपत्र में पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(द) "पर्यटक" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है, जिनके अन्तर्गत तीर्थ यात्री भी हैं, जो भारत के किसी भाग या भारत के बाहर से हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी पर्यटन क्षेत्र की यात्रा पर आए हों ; और

(ध) "यात्रा एजेंट" से आर्थिक प्रतिफल हेतु पर्यटकों के लिए यात्रा, शिविरों, पर्यटन संचालन या यात्रा के अन्य प्रबन्धों के कारबार में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है और पर्यटक गाइड और शिकार-आउटफिटर इसमें अन्तर्गत हैं ।

स्पष्टीकरण :

"यात्रा प्रबन्ध" पद से अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(क) परिवहन के लिए प्रबन्ध ;

(ख) खान-पान सहित या रहित आवास के लिए प्रबन्ध ; और

(ग) अन्य सेवाएं करना, जैसे कि क्रीड़ा और खेल पर्यटक के व्यक्तिगत सामान की प्राप्ति या निर्गम या पर्यटक के फोटोचित्र लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता ।

अध्याय-2

व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण

4. (1) इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी का कारबार करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे कारबार को प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण ।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात मेलों और त्यौहारों के दौरान अस्थायी रूप से लगाई गई मण्डियों में अधिसूचित वस्तुओं के विक्रय को लागू नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, धारा 3 के खण्ड (2) के अधीन ऐसी वस्तु के अधिसूचित किए जाने की तारीख को, किसी पर्यटन क्षेत्र में किसी अधिसूचित वस्तु के विक्रय के कारबार को पहले से ही करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त तारीख से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदक का आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर उसका निपटान किया जाएगा और इसमें असफल रहने पर, आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा।

व्यवहारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र। 5. जब तक धारा-6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, विहित प्राधिकारी, व्यवहारी का नाम और विवरण इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट करने का निदेश देगा और आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विहित प्ररूप में व्यवहारी को प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

व्यवहारी को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार। 6. विहित प्राधिकारी, किसी व्यवहारी को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि वह भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन 1860 का किसी अपराध या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, 45 तस्करी या मुनाफाखोरी या खाल और औषधियों का अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;
 - (ख) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उन्माचित नहीं किया गया है;
 - (ग) यदि उसका नाम धारा-7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में उल्लिखित आधार पर रजिस्टर से हटाया गया है और ऐसे हटाए जाने की तारीख से तीन मास व्यतीत नहीं हुए हों;
 - (घ) यदि विहित प्राधिकारी की राय में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के लिए अभिलिखित किए जाने वाला पर्याप्त आधार है ;
- परन्तु रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन को तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

व्यवहारी के नाम को रजिस्टर से हटाना 7. विहित प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर लिखित आदेश द्वारा रजिस्टर से व्यवहारी का नाम हटा सकेगा और उसके प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि वह व्यवहारी नहीं रहता है ;
- (ख) यदि वह भारतीय दण्डसंहिता, 1860, के अध्याय 14 और 16 के अधीन 1860 का किसी अपराध या इस अधिनियम के किसी उपबन्धों के अधीन या जमा- 45 खोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाल और औषधियों का अपमिश्रण या

अष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है;

- (ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (घ) यदि उसके विरुद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और साबित होती है; और
- (ङ) यदि विहित प्राधिकारी द्वारा उसे काली सूची में डाला जाता है।

(2) कोई व्यवहारी जिसका नाम उप-धारा (1) के अधीन रजिस्टर से निकाल दिया जाता है, तत्काल व्यवहारी नहीं रहेगा।

8. (1) विहित प्राधिकारी, अनाचार की शिकायत के साबित होने पर या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अन्य अपराध के लिए अनाचार की प्रकृति या अपराध की गम्भीरता पर विचार करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके किसी व्यवहारी को काली-सूची में ला सकेगा।

व्यवहारियों को काली सूची में डालना।

(2) काली-सूची में लाए गए व्यवहारी की विशिष्टियां उस काली-सूची में लाने के आदेश के अन्तिम होने पर, सभी पर्यटन क्षेत्रों में सहज-दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी और सभी यात्रा, व्यापार और अन्य सम्बन्धित संगठनों, भारत में विदेशी दूतावासों और विदेशों में भारतीय दूतावासों और अन्य महत्वपूर्ण सम्बन्धित माध्यमों को अधिसूचित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई ऐसे व्यवहारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभियोजित करने के लिए संरक्षण प्रदान नहीं करेगी।

(4) यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि काली-सूची से व्यवहारी को हटाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह कारणों को अभिलिखित करके उस सूची से हटाने के आदेश दे सकेगा और विहित फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा।

9. धारा-7 के अधीन रजिस्टर से व्यवहारी का नाम हटाने या धारा-8 के अधीन उसे काली-सूची में लाने से पूर्व विहित प्राधिकारी व्यवहारी को उस आधार या उन आधारों का नोटिस देगा जिन पर कार्रवाई करना और व्यवहारी की उपस्थिति में, उसके विरुद्ध कारण बताना का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने पर, जांच करना प्रस्तावित है।

नाम हटाने और व्यवहारी को काली-सूची में डालने का नोटिस।

अध्याय-3

होटलों का रजिस्ट्रीकरण

10. (1) पर्यटन क्षेत्र में होटल चलाने का इच्छुक व्यक्ति, होटल चलाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

होटलों का रजिस्ट्रीकरण।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, धारा-3 के खण्ड (थ) के अधीन अधिसूचना जारी की जाने की तारीख को पहले से पर्यटन क्षेत्र में होटल चला रहा कोई व्यक्ति, उपयुक्त तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

होटल के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र। 11. विहित प्राधिकारी, जब तक धारा-12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, होटल और होटल चलाने वाले के नाम और विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने का निदेश देगा और होटल चलाने वाले को विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

होटल को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार। 12. विहित प्राधिकारी, होटल को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि होटल चलाने वाला भारतीय दण्डसंहिता, 1860 के अध्याय XIV और XVI के अधीन किसी अपराध या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन, या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य या औषधियों के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश की समाप्ति से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;
- (ख) यदि होटल चलाने वाले को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (ग) यदि होटल चलाने वाले का नाम धारा-13 के खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) में उल्लिखित आधार पर, उस रजिस्टर से हटाया गया है और ऐसे हटाए जाने की तारीख से तीन मास व्यतीत नहीं हुए हैं;
- (घ) यदि परिसर, विहित स्तर के अनुरूप नहीं हैं;
- (ङ) यदि होटल चलाने वाले के पास तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस द्वारा धारित की जाने वाली अपेक्षित अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र नहीं हैं; और
- (च) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के लिए अभिलिखित किए जाने वाला पर्याप्त आधार हैं :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

होटल के नाम को रजिस्टर से हटाना।

13. विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर रजिस्टर से होटल का नाम हटा सकेगा और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि होटल चलाने वाला पर्यटन क्षेत्र में होटल चलाना बन्द कर देता है, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;
- (ख) यदि होटल चलाने वाला, भारतीय दण्डसंहिता, 1860 के अध्याय XIV और XVI या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य या औषधियों के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से दो वर्ष व्यतीत न हुए हों;
- (ग) यदि होटल चलाने वाले को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया गया है;

- (घ) यदि होटल चलाने वाला इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन करने में विफल रहता है;
- (ङ) यदि होटल चलाने वाला ऐसे ठहरने वाले को निकालने में विफल रहता है या होटल में ऐसे ठहरने वाले को जानबूझ कर रखता है जो पार्श्वस्थ भवन के अन्तःवासियों के लिए न्यूसस बन रहा हो;
- (च) यदि होटल चलाने वाले के विरुद्ध अनाचार की शिकायत प्राप्त होती है और साबित हो जाती है;
- (छ) यदि होटल को धारा-14 के अधीन काली-सूची में डाला गया हो; और
- (ज) यदि होटल चलाने वाला, क्षेत्र का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के अधिमान में, क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को होटल में वास-सुविधा देता है।

14. (1) विहित प्राधिकारी, अनाचार की शिकायत साबित होने पर या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अन्य अपराध के लिए, कारणों को अभिलिखित करके अनाचार के स्वरूप या अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए होटल को एमी अवधि के लिए, जो छः मास तक की हो सकेगी, काली-सूची में डाल सकेगा।

होटलों को काली-सूची में डालना।

(2) काली-सूची में डाले गए होटल की विशिष्टियां सभी पर्यटन क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित तथा सभी यात्रा, व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित संगठनों, भारत में विदेशी दूतावासों और विदेश में भारतीय दूतावासों को अधिसूचित की जाएंगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने से ऐसे होटल चलाने वाले को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करेगी।

(4) यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि होटल चलाने वाला को काली-सूची से निकालने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे ऐसी सूची से निकालने के आदेश दे सकेगा और विहित फीस के संदाय पर, नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा और उसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित कर सकेगा।

15. धारा 13 के अधीन रजिस्टर में होटल का नाम हटाए जाने या धारा-14 के अधीन उसे काली-सूची में डाले जाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, होटल चलाने वाले को उस आधार या उन आधारों की बाबत नोटिस देगा जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और होटल चलाने वाले को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उसकी उपस्थिति में जांच करेगा।

नाम हटाने और होटल को काली-सूची में डालने का नोटिस।

16. विहित प्राधिकारी, विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति के परामर्श से :—

दरनियतन।

(क) होटल के स्तर (स्टैंडर्ड) और भोजन की क्वालिटी, वास-सुविधा तथा सेवा की आनुपातिक युक्तियुक्त अधिकतम दर तथा सेवा प्रभार, यदि कोई हों, नियत कर सकेगा;

जिन्हें होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों या अन्य ग्राहकों से मौसम (सीजन) और "मंदी : मौसम" के दौरान, होटल चलाने वाला, खान-पान या ठहरने या दोनों के लिए, प्रभारित कर सकेगा :

परन्तु ठहरने के लिए दरें प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट वास-सुविधा और ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, नियत की जाएंगी;

(ख) होटल में दैनिक और मासिक आधार पर ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए वास-सुविधा की प्रतिशतता नियत कर सकेगा;

- (ग) होटल में प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट वास-सुविधा और ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत कर सकेगा;
- (घ) दैनिक और मासिक आधार पर ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए पृथक् रूप से उचित दरें नियत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, ऐसा ठहरने वाला व्यक्ति, जो एक मास से कम अवधि के लिए होटल में वास-सुविधा आरक्षित करने के लिए सहमत हो, दैनिक आधार पर ठहरने वाला व्यक्ति समझा जाएगा।

उचित दरों का पुनरीक्षण। 17. विहित प्राधिकारी समय-समय पर धारा-16 के अधीन नियत उचित दरों (वास-सुविधा की प्रतिशतता या ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या) का पुनरीक्षण कर सकेगा।

विहित अधिकारी द्वारा उचित दरें, वास-सुविधा की प्रतिशतता और ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत न की गई हो, होटल चलाने वाला इन्हें नियत करेगा और प्रत्येक वर्ष की तारीख 31 मार्च तक विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और मौसम (सीजन) और "मन्दी के मौसम" की अवधि के लिए पृथक् दरें नियत की जाएंगी।

नियतन। 19. जहां विहित प्राधिकारी ने धारा 16 या 17 के अधीन उचित दरें, वास-सुविधा की प्रतिशतता या ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत कर दी हो या प्राधिकारी ने दरें आदि नियत न की हों, वहां, होटल चलाने वाला उचित दरों, वास-सुविधा की प्रतिशतता, ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या की सूचना होटल में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और होटल चलाने वाले का एजेंट भी विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसी सूचना की प्रति अपने पास रखेगा।

सूचना प्रदर्शित करना। 20. (1) किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई होटल चलाने वाला नियत उचित दरों से अधिक राशि प्रभारित नहीं करेगा।

उचित दरों से अधिक प्रभारों का वसूलीय होना।

(2) ठहरने वाले व्यक्ति द्वारा उचित दर से अधिक संदत्त की गई राशि उस द्वारा इसके संदाय की तारीख से एक वर्ष के भीतर होटल चलाने वाले से किसी भी समय वसूलीय होगी और वसूली के किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठहरने वाले व्यक्ति द्वारा होटल चलाने वाले को देय किसी राशि में समायोज्य होगी।

उचित दर संदत्त किए जाने पर वेदखल न किया जाना।

21. कोई भी होटल चलाने वाला, ठहरने वाले को, वेदखल नहीं करेगा या खान-पान या किसी अन्य सेवा से इन्कार नहीं करेगा जब तक वह नियत दर का संदाय करता है या संदाय करने के लिए तैयार और तत्पर है और अपने करार की अन्य शर्तों का, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, पालन और कार्यान्वयन करता है:

परन्तु जहां धारा 16 या 17 के अधीन विहित प्राधिकारी ने क्रमशः दैनिक और मासिक तौर पर ठहरने वालों की वास-सुविधा की प्रतिशतता नियत या पुनरीक्षित की है वहां होटल चलाने वाला किसी दैनिक तौर पर ठहरने वाले को वास-सुविधा से इन्कार कर सकेगा यदि ऐसे वर्ग से सम्बन्धित वास-सुविधा पूर्ण रूप से भरी हुई है।

होटल चलाने वाला कब कब्जा वापस ले सकेगा।

22. इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, होटल चलाने वाला उस द्वारा दी गई वास-सुविधा का, विहित प्राधिकारी से निम्नलिखित आशय का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने पर कब्जा वापस कर लेने का हक्कदार होगा कि:—

(क) ठहरने वाला ऐसे आचरण का दोषी है जो पार्श्वस्थ या पड़ोस में किसी

- ठहरने वाले के लिए 'न्यूसेन्स' या परेशानी पैदा करता है; या
- (ख) वास-सुविधा, व्यक्तिगत और वास्तविक रूप में होटल के स्वामी द्वारा या तो अपने अधिभोग के लिए या किसी अन्य हेतु से जो विहित प्राधिकारी द्वारा समाधानप्रद माना जाए, अपेक्षित है; या
- (ग) मासिक तौर पर ठहरने वाला होटल में दिए गए खान-पान, आवास या अन्य सेवा-प्रकारों का संदाय करने में तीन मास तक अभ्यासतः अनियमित या व्यतिक्रमी रहा है; या
- (घ) ठहरने वाला वास-सुविधा के बारे में किए गए करार की अवधि की समाप्ति पर, उसे खाली करने में विफल रहा है:
- परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी उस समय वास-सुविधा में दैनिक और मासिक तौर पर ठहरने वालों के लिए खाली वास-सुविधा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा; या
- (ङ) ठहरने वाले ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो उस को दी गई वास-सुविधा के प्रयोजन से असंगत है या जो होटल चलाने वाले के उसमें हित को प्रति-कूल और सारभूत रूप से प्रभावित करता है:
- परन्तु प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व, ठहरने वाले को अपने मामले को प्रस्तुत करने का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किया जाएगा।

23. प्रत्येक होटल चलाने वाला होटल में निवास करने वाले व्यक्ति और अन्य ग्राहकों को ब्योरेवार बिल पेश करेगा और सभी संदायों की अभिस्वीकृति की पावती देगा।

होटल चलाने वाले द्वारा ब्योरेवार बिलों का पेश किया जाना।

24. यदि होटल चलाने वाला विशेष दर पर बुकिंग का पुष्टीकरण करता है, तो यह उसी दर पर सकारी जाएगी भले ही उस व्यक्ति की पहुंच के समय जिसके लिए वास-सुविधा बुक की गई है, जबल उच्च दर पर ही वास-सुविधा उपलब्ध है।

होटल चलाने वाला जब विशेष दर पर बुकिंग का पुष्टीकरण कर सकेगा।

25. विहित प्राधिकारी या उस द्वारा समय-समय पर होटल के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पूर्वं नोटिस सहित या रहित परिसर में जाने की अनुशा होगी।

नोटिस सहित या रहित निरीक्षण।

अध्याय-4

यात्रा एजेंट

26. (1) कोई भी व्यक्ति, पर्यटन क्षेत्र में यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड का कार-बार नहीं करेगा, जब तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्री-कृत नहीं है।

यात्रा एजेंटों, भ्रमण एजेंटों और गाइडों का रजिस्ट्रीकरण।

(2) पर्यटन क्षेत्र में यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड के रूप में कार्य करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विहित, प्राधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, धारा 3 के खण्ड (थ) के अधीन अधिसूचना जारी की जाने की तारीख को पर्यटन क्षेत्र में, यात्रा एजेंट के रूप में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति उक्त तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा; ऐसा न होने पर आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

यात्रा एजेंटों
आदि का
रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र।

27. (1) विहित प्राधिकारी, जब तक धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड के नाम और विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज करने का निदेश देगा और, यथास्थिति, यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

यात्रा एजेंट,
भ्रमण एजेंट
या गाइड
को रजिस्ट्री-
कृत करने
से इन्कार।

28. विहित प्राधिकारी, यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड को निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि वह कोई विहित अर्हता न रखता हो;
- (ख) यदि वह भारतीय दंड संहिता, 1860 के, अध्याय 15 और 16 में अधीन किसी अपराध का, या इस अधिनियम में किसी उपबन्ध में अधीन, या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाली या औषधियों का अपमिश्रण या भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्याप्तान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हों;
- (ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिनांकित घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (घ) यदि इस अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित आधार पर, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और ऐसा हटाए जाने की तारीख से तीन मास व्यतीत नहीं हुए हैं; और
- (ङ) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के लिए अभिलिखित किए जाने वाला पर्याप्त आधार है:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन को तब तक नामजूर नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

यात्रा एजेंट
आदि का
नाम रजि-
स्टर से
हटाना।

29. विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित में से किसी आधार पर, यथास्थिति, यात्रा एजेंट, भ्रमण एजेंट या गाइड का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा और उसका प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यदि वह पर्यटन क्षेत्र में यात्रा एजेंट के रूप में कार्यरत नहीं रहता है;
- (ख) यदि वह भारतीय दंड संहिता, 1860 में अध्याय 14 और 16 में अधीन किसी अपराध या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी,

1960 का 45
20

1860 का 45

तस्करी या मृताफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश की समाप्ति से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;

- (ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (घ) यदि उसके विरुद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और साबित हो जाती है; और
- (ङ) यदि विहित प्राधिकारी द्वारा उसे काली सूची में डाला जाता है।

30. (1) विहित प्राधिकारी, अनाचार की शिकायत के साबित होने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए, अनाचार की प्रकृति या अपराध की गम्भीरता पर विचार करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके किसी यात्रा एजेंट को ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित प्राधिकारी उचित समझे, काली-सूची में डाल सकेगा।

यात्रा एजेंटों को काली सूची में डालना।

(2) काली सूची में डाले गए यात्रा एजेंट की विशिष्टियाँ सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी और सभी यात्रा, व्यवसायी और अन्य सम्बन्धित संगठनों, भारत में विदेशी दूतावासों और विदेश में भारतीय दूतावासों को अधिसूचित की जाएंगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई ऐसे यात्रा एजेंटों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभियोजित करने के लिए संरक्षण प्रदान नहीं करेगी।

(4) यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि काली-सूची से यात्रा एजेंट को हटाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह कारणों को अभिलिखित करके उसे ऐसी सूची से हटाने के आदेश दे सकेगा और विहित फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा।

31. धारा 29 के अधीन रजिस्टर से यात्रा एजेंट का नाम हटाने या धारा 30 के अधीन उसे काली-सूची में डालने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, यात्रा एजेंट को उस आधार या उन आधारों का नोटिस देगा जिन पर कार्रवाई करना और उस व्यक्ति की उपस्थिति में, उस विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने पर, जोच करना प्रस्तावित है।

यात्रा एजेंटों को काली सूची में डालने और हटाने का नोटिस।

32. विहित प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उचित दरें नियत कर सकेगा जिन्हें यात्रा एजेंट उसे इस रूप में लगाए गए व्यक्ति से उस द्वारा की गई सेवाओं के लिए प्रभारित कर सकेगा।

दर नियतन।

33. विहित प्राधिकारी, धारा 32 के अधीन नियत उचित दरों को समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगा।

उचित दरों का पुनरीक्षण।

34. जब तक विहित प्राधिकारी ने उचित दरें नियत न की हों, यात्रा एजेंट इन्हें नियत करेगा और प्रत्येक वर्ष मार्च 31 वें दिन तक इन को विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

यात्रा एजेंटों द्वारा दर नियत और अधिसूचित किया जाना।

सूचना प्रदर्शित
करना।

35. जहां विहित प्राधिकारी ने धारा 32 या धारा 33 के अधीन उचित दरों को नियत किया है या पुनरीक्षित किया है या उस दशा में भी जिस में विहित प्राधिकारी ने दरें नियत नहीं की हैं यात्रा एजेंट अपने कार्यालय या सहज-दृश्य स्थान पर उचित दरों का नोटिस और ऐसी सूचना जो विहित की जाए, प्रदर्शित करेगा।

उचित दर से
अधिक संदत्त
प्रभार।

36. (1) किसी करार के विरुद्ध होते हुए भी, कोई भी यात्रा एजेंट नियत दर से अधिक दर प्रभारित नहीं करेगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा उचित दर से अधिक संदत्त की गई कोई भी राशि, यात्रा एजेंट से, ऐसे संदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वसूलीय होगी और वसूली या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यात्रा एजेंट को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि में समायोजित की जा सकेगी।

सेवा करने से
इन्कार
करना।

37. कोई भी यात्रा एजेंट, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं देने से इन्कार नहीं करेगा जब तक वह नियत दरों का संदाय करता है और संदाय करने के लिए तैयार और तत्पर है।

यात्रा एजेंट
द्वारा ब्योरे
वार बिल
का पेश किया
जाना।

38. प्रत्येक यात्रा एजेंट, उसकी सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ब्योरेवार बिल पेश करेगा और सभी संदायों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति के रूप में रसीद देगा।

यात्रा एजेंट
द्वारा बख्शीश
आदि न
मांगना।

39. यात्रा एजेंट किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसे इस रूप में लगाता है या किसी ऐसे होटल चलाने वाले से, जिसके होटल में ऐसा व्यक्ति निवास करता है या निवास करने का इरादा रखता है, इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित के सिवाय, कोई बख्शीश, उपदान, उपहार या बक्शीशन की मांग नहीं करेगा।

अध्याय-5

अपील और पुनरीक्षण

अपील।

40. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को होगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश की संसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त 90 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्तियुक्त कारणों द्वारा निवारित हुआ है।

(3) अपीलार्थी को अधिवक्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट द्वारा उसके प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा और विहित प्राधिकारी का ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे।

(4) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

41. सरकार द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यक्तिगत पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के सहीकरण, वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगा : पुनरीक्षण।

परन्तु आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा अभिलेख नहीं मंगाया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट द्वारा सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय-6

अपराध और शास्तियां

42. इस अधिनियम के अधीन समुचित रजिस्ट्रीकरण के बिना या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में, व्यवहारी, होटल चलाने या यात्रा एजेंट के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, छः मास से अनधिक अवधि के कारावास से या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से, और यदि उल्लंघन लगातार हो तो कम से कम सौ रुपये प्रतिदिन और अधिक से अधिक एक हजार रुपये प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित होटल और रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति द्वारा विहित रीति से किए गए, यथास्थिति, होटल या यात्रा एजेंसी के वर्गीकरण पर निर्भर करेगा। रजिस्ट्रीकरण में व्यतिक्रम के लिए शास्ति।

स्पष्टीकरण:—ऐसा व्यक्ति जिसने विहित अवधि के भीतर आवेदन किया हो और यह आवेदन निपटाने के लिए लम्बित हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रमी नहीं होगा।

43. यदि इस अधिनियम के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, जानबूझ कर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सार-भूत तथ्य को छुपाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा। मिथ्या कथन के लिए शास्ति।

44. कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपये से अधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। प्रमाण-पत्र का समनुदेशित न किया जाना।

व्यक्तियों को
मांगने पर
प्रमाण-पत्र
का दिखाया
जाना।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, मांगने पर, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और दिखाएगा, अर्थात् :—

(क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी; और

(ख) कोई वास्तविक ग्राहक।

(2) कोई व्यक्ति जो मांगने पर अपना प्रमाण-पत्र दिखाने या मांगने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी द्वारा इसे पढ़न की अनुज्ञा देने से इन्कार करता है, पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

अनाचार
के लिए
शास्ति।

46. कोई होटल चलाने वाला या यात्रा एजेंट, जो पर्यटन क्षेत्र में अनाचार करता है या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

विधियुक्त
प्राधिकारियों
को बाधा
पहुंचाना।

47. यदि कोई व्यक्ति, जानबूझ कर विहित प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी शक्ति के प्रयोग में या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अनुसरण में, बाधा डालता है या प्रतिरोध करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

मामलों
का संक्षेपतः
विचारण
करने की
न्यायालयों
की शक्ति।

48. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या अन्य प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट (उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत) द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहां तक हो सके दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों को शामिल करते हुए) के उपबन्ध लागू होंगे :

परन्तु जब इस धारा के अधीन विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके दौरान मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किन्हीं कारणों से उसका संक्षेपतः विचारण अवांछनीय है, तो मैजिस्ट्रेट, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को जिसका परीक्षण किया गया है पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने में अग्रसर होगा।

कार्यवाहियों
का संस्थित
किया जाना।

49. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, विहित प्राधिकारी या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

विहित प्राधि-
कारी की
समन करने
और साक्षियों

50. विहित प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई करते समय, निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(i) परिवादी या ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है और उसके इस सम्बन्ध में अपक्षित साक्षियों को समन करने और हाजिर करवाने;

(ii) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

और अन्य
व्यक्तियों को
हाजिर कर-
वाने की शक्ति।

(iii) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करना;
और किसी भी व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य सारभूत प्रतीत होता हो, स्वप्रेरणा से समन करना और उसका परीक्षण करना।

51. (1) विहित प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे अपराध के लिए शमन के रूप में कोई राशि स्वीकार कर सकेगा और ऐसी प्राप्त की गई राशि से ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो उस विस्तार तक, जिसे विहित प्राधिकारी युक्तियुक्त समझे, प्रतिकर दे सकेगा।

अपराधों का शमन।

(2) अपराध के शमन पर, अभियुक्त के विरुद्ध इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि न्यायालय में उससे विरुद्ध पहले से कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो, तो शमन दोषमुक्ति के रूप में प्रभावी होगा।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

52. (1) जब कोई ऐसा कार-बार, जिसके लिए कि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र लिया है, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को न्यागत हो जाता है, या इस अधिनियम के अधीन इस विषय में रजिस्टर में की गई किसी विशिष्टि में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे न्यागत या परिवर्तन की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, ऐसे तथ्य को लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

परिवर्तनों की अधि-सूचना।

(2) विहित प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा जिसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा यदि इस अधिनियम के अधीन उत्तरवर्ती, रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र नहीं है।

53. जब इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया जाए तो प्रमाण-पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दीकरण आदेश की विहित रीति में तामील की तारीख से सात दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।

रजिस्ट्री-करण प्रमाण-पत्र का वापस किया जाना।

54. यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र गुप्त, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक व्यक्ति के आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर, द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र।

55. इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र इसके जारी या नवीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात्, समाप्त हो जाएगा और विहित प्राधिकारी उसे दिए गए आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर एक समय पर तीन वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा, जब तक कि :—

प्रमाण-पत्र का नवीकरण

(i) प्रमाण-पत्र धारक ने अपना कारबार बन्द न कर दिया हो; या

- (ii) प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन ऐसी निरर्हता से ग्रस्त न हो जिससे वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है; या
- (iii) प्रमाण-पत्र धारक का नाम रजिस्टर से हटा न दिया गया हो और ऐसी अवधि का अवसान न हो गया हो जिसके लिए उसका नाम हटाया गया हो; या
- (iv) प्रमाण-पत्र धारक काली सूची में न डाला गया हो और काली सूची में डालने का आदेश प्रतिसंहत न कर दिया गया हो ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रदर्शित रखा जाना । 56. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, इससे धारक व्यक्ति द्वारा उसके कारबार के मुख्य स्थान में सहज-दृश्य स्थान पर रखा जाएगा और यदि उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो या वह किसी विशेष स्थान से अन्यथा कारबार चलाता हो, तो वह यह प्रमाण-पत्र अपने पास ही रखेगा ।

रजिस्टर से हटाए गए व्यक्तियों की सूची का प्रकाशन । 57. विहित प्राधिकारी, समय-समय पर, उन व्यक्तियों और होटल के नाम और पते, जिनके नाम रजिस्टर से हटाए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार किया गया है, राजपत्र में और ऐसी रीति में जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा ।

निरीक्षण करने की शक्ति । 58. विहित प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, पर्यटन क्षेत्र में हर युक्तियुक्त समय पर परिसरों का जिनमें यात्रा एजेंट या व्यवहारी अपना कारबार करता है या किसी ऐसे परिसर का जिसमें होटल चलाया जा रहा हो, निरीक्षण कर सकेगा और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए किसी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

विहित प्राधिकारी के समक्ष कार्य-वाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना । 59. इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्य-वाहियां समझी जाएंगी ।

परित्याग । 60. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

अन्य व्यक्तियों को अधिनियम को लागू करने की सरकार की शक्ति । 61. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध ऐसे अपवाद, अनुकूलीकरण या उपांतरण सहित, जैसे आवश्यक समझे जाएं, पर्यटन क्षेत्र में आउटडोर फोटोग्राफी, गृह नौका, डोंगो, बेदिंग बोट्स, शिकारे, आटोमोबाइल व्हीकल्ज, टांगे, डंडी, पिड्डू, टट्टू को किराए पर देने या उन्हें चलाने के कारबार में लगे व्यक्तियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को लागू होंगे जो विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और विहित प्राधिकारी, की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रचारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा ।

62. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वशामो शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

- (क) होटल चलाने वालों या यात्रा एजेंटों द्वारा कारबार के संचालन के लिए, रजिस्ट्रारों, पुस्तकों और प्ररूपों का रखा जाना;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का प्ररूप;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन नोटिस देने की रीति;
- (ङ) रजिस्ट्रार से हटाए गए या रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति ;
- (च) होटलों और यात्रा एजेंटों का वर्गीकरण;
- (छ) यात्रा एजेंटों और गाइडों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं;
- (ज) रजिस्ट्रार से हटाए गए व्यक्तियों और होटलों के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति;
- (झ) वह रीति जिसमें व्यवहारी, होटल चलाने वाले या यात्रा एजेंट को काली सूची में डाला जाएगा और ऐसे व्यवहारी, होटल चलाने वाले या यात्रा एजेंटों का नाम और पते प्रकाशित किए जाएंगे;
- (ञ) वह स्थान जहां विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच करेगा; और
- (त) वे सभी मामले जिन्हें इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से विहित करना अपेक्षित है ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे ।

1970 का 22

63. हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ होटल्स ऐण्ड ट्रेवल एजेंट्स ऐक्ट, 1970 का एतद्वारा निरसन किया जाता है :

निरसन और व्यावृत्तियां ।

परन्तु उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना, मंजूर किया गया प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा, या प्रारम्भ या जारी की गई कार्यवाहियां भी हैं), इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जाएंगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पर्यटन ने नया आयाम अर्जित कर लिया है और अदृश्य आयात के साथ यह मुख्य उद्योगों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। होटलों, यात्रा एजेंटों और फोटोग्राफरों आदि की बहुत वृद्धि हो गई है। इस विषय में विद्यमान अधिनियमिति अर्थात् "हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन आफ होटल्स एण्ड ट्रेवल एजेंट्स ऐक्ट, 1970" राज्य में पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं से निपटाने के लिए अपूर्ण है। विद्यमान उपबन्ध को तुरन्त नया रूप देने की आवश्यकता है ताकि पर्यटन एजेंसियों से, जोकि छल, दलाली, प्रतिरूपण, ज्यादा कीमतें वसूल करने जैसे अनाचारों में संलिप्त हैं और पर्यटकों को वास सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही हैं, या वास्तविक पर्यटकों से अन्यथा दूसरे व्यक्तियों को दैनिक मिराए पर वास-सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, प्रभावपूर्ण ढंग से निपटा जा सके। विद्यमान अधिनियम में व्यवहारियों, होटलों और यात्रा एजेंटों आदि को काली सूची में डालने और प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, विहित शास्तियां बहुत कम हैं और वर्तमान परिस्थितियों में उनमें वृद्धि करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

राजकृष्ण गौड़,
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

अप्रैल 4, 1988.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों के अधिनियमित किए जाने पर, खण्ड 4, 10 और 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य फीस के रूप में और कोर्ट फीस से तथा विधेयक के किसी भी उपबन्ध के अधीन किए गए अपराधों के लिए शास्तियों से, अनुमानतः 5.50 लाख रुपये की वार्षिक आबर्ती आय प्राप्त होनी सम्भाव्य है। इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन में 3.50 लाख रुपये तक का अतिरिक्त व्यय अन्तर्बलित है (जिसमें से 1.00 लाख रु० का आबर्ती और 2.50 लाख रु० आबर्ती व्यय होगा) क्योंकि विद्यमान तंत्र (मशीनरी) में वृद्धि करनी पड़ेगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

खण्ड 62, उसमें वर्णित मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सरकार को सशक्त करता है। बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त अधीन हैं और ये विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे। प्रस्तावित प्रत्योजन आवश्यक और सामान्य है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[पर्यटन विभाग नस्ति संख्या 5-3/86 टी० ए० एस० एम० (सचि०)]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1988 की विषय-वस्तु में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 5 of 1988.

THE HIMACHAL PRADESH REGISTRATION OF TOURIST TRADE BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide facilities to the tourists and for registration of persons dealing with them and for matters connected therewith.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. (1) This Act shall not apply to a hotel, tourist rest house, dak bungalow, sarai, inn or any institution or premises managed or run by the Government or a local authority.

Exemptions.

(2) The State Government may direct that all or any of the provisions of this Act shall not, subject to such conditions and terms as it may specify, apply generally—

- (i) to premises used for a public purpose of a charitable nature or to any class of premises used for such purposes ;
- (ii) to premises held by a public trust for a religious or charitable purpose and let out at a nominal rent; or
- (iii) to premises held by a public trust for a religious or charitable purpose and administered by a local authority.

(3) The State Government may, also by order, direct that all or any of the provisions of Chapter-III shall not apply to such hotels or institutions, or such class of hotels or institutions, subject to such terms and conditions, if any, as may be specified in the order.

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions.

- (a) “black-list” means a list maintained and exhibited for dealers hotel-keepers, travel agents, guides and excursion agents who have been black-listed under the provisions of this Act;

- (b) "certificate of registration" means a certificate issued under this Act;
- (c) "dealer" means a person carrying on in a tourist area the business of selling any notified article, whether whole-sale or retail, and includes his agent or employee transacting business on his behalf;
- (d) "excursion agent" means a person engaged in or engaging himself in arranging excursions, tours or picnics for a tourist or tourists ;
- (e) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (f) "guide" means a person who engages himself as a paid guide for tourists :

Provided that no person shall be eligible to be registered as a guide, unless he possesses such qualifications as may be prescribed :

Provided further that notwithstanding any prescribed qualifications the persons who were working as guides, before the commencement of this Act, shall *facto* be registered as such guides :

- (g) "hotel" means any premises or part of premises including a house-boat, restaurant, bar or a tent where lodging with or without board or any kind of eatables or beverages or other services are by way of business provided for a monetary consideration, and includes such premises as are given on rent during the season ;
- (h) "hotelkeeper" means any person who owns or operates a hotel as proprietor and includes a person managing or operating the affairs of a hotel on behalf of the proprietor;
- (i) "local authority" means the Deputy Commissioner, Municipal Corporation, Municipal Committee, Notified Area Committee, Panchayat and Public Trust in the respective jurisdiction;
- (j) "malpractice" includes cheating, touting, impersonation, obstruction in allowing free choice for shopping or stay or travel management; charging a price higher than that displayed on the label, or rent or remuneration higher than that fixed under this Act; failure to display price label on each article; failure to display the rent list; failure to give cash memos; wilful failure to execute an order within the stipulated period and according to the terms agreed upon; and failure to provide accommodation to the tourists when available or providing accommodations during the season on daily/monthly rent to persons other than tourists.

Explanation-I.—For the purposes of this clause, "labelled price" (the price displayed on the label on notified article) shall be such reasonable price as may be fixed by the prescribed authority.

Explanation-II.—The expression "touting" means coercing for shopping, accommodation, transportation, sight-seeing or pestering for any particular premises, persons, establishment, dealer, manufacturer or any other service connected with tourism with the consideration of personal benefit;

- (k) "notified article" means any article notified in the Official Gazette for the purposes of this Act, and for different tourist areas, different articles may be notified ;
- (l) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

- (m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (n) "prescribed authority" means the authority notified as such by the Government, provided that different authorities may be notified for different areas and for different provisions of this Act ;
- (o) "season" means the period from September 16 to June 30 and the rest of the period of the year will constitute "off season";
- (p) "specified accommodation" in relation to a hotel means accommodation (by whatever name called) other than the accommodation available in exclusive rooms, to be provided to persons staying in a hotel and which is of such a class as may be determined by the prescribed authority from time to time;
- (q) "tourist area" means any area notified by the Government in the Official Gazette to be a tourist area for the purposes of this Act ;
- (r) "tourist" means a person or group of persons, including pilgrims, visiting any tourist area in the State of Himachal Pradesh from any part of India or outside India; and
- (s) "travel agent" means a person engaged in the business of making travel, camping, tour operating or other travel arrangements for tourists for a monetary consideration and includes a tourist guide and a shikar outfitter ;

Explanation.—The expression "travel arrangements, includes—

- (a) arrangements for transportation ;
- (b) arrangements for lodging with or without board ; and
- (c) rendering other services, such as assistance for providing convenience for game and sports or receipt or despatch of personal belongings of a tourist or taking photograph(s) of a tourist.

CHAPTER II

REGISTRATION OF DEALERS

4. (1) Every person intending to carry on business of a dealer under this Act shall before he commences such business, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner : Registration of dealers.

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the sale of notified articles in fairs and temporary markets organised during festivals.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) any person already carrying on business of selling any notified article in a tourist area on the date on which such article is notified under clause (k) of section 3, shall apply for registration under this Act within three months from the aforesaid date.

(3) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of three months from the date of receipt of the application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

5. The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 6, direct that the name and the particulars of the dealer be entered in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate to the dealer in the prescribed form within a period of three months from the date of receipt of the application. Certificate of registration of a dealer.

Refusal to register a dealer.

6. The prescribed authority may refuse to register a dealer under this Act on any of the following grounds, namely:—

- (a) if he is convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food and drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him ;
- (b) if he has been declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
- (c) if his name has been removed from the register on the ground mentioned in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 7 and three months have not elapsed since the date of such removal ;
- (d) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground to be recorded in writing, for refusing registration ;

45 of 1860

Provided that no application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

Removal of the name of a dealer from the register.

7. (1) The prescribed authority may, after affording a reasonable opportunity of being heard, by an order in writing, remove the name of a dealer from the register and cancel his certificate on any of the following grounds, namely:—

- (a) if he ceases to be a dealer;
- (b) if he is convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under the provisions of this Act or of any offence punishable under the law providing for prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption ;
- (c) if he is declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged ;
- (d) if any complaint of malpractice is received and proved against him; and
- (e) if he is black-listed by the prescribed authority.

45 of 1860

(2) Any dealer whose name is removed from the register under sub-section (1) shall forthwith cease to be a dealer.

Black-listing of dealers.

8. (1) The prescribed authority may on proof of complaint of malpractice or for any other offence committed under this Act, for reasons to be recorded, black-list a dealer, after taking into consideration the nature of malpractice or gravity of the offence, for a period which may extend to six months.

(2) The particulars of a dealer black-listed shall be exhibited at conspicuous places in all tourist areas and notified to all travel, trade and other concerned organisations, foreign missions in India and Indian missions abroad and other important concerned channels after the order black-listing him has become final.

(3) The action taken under sub-section (1) shall not protect such dealer from being prosecuted under the provisions of this Act.

(4) If the prescribed authority is satisfied that there are sufficient grounds for removal of a dealer from the black-list, it may after recording

the reasons, order his removal from the list and issue afresh certificate of registration on payment of prescribed fee and notify the same for the information of all concerned.

9. Before removing the name of a dealer from the register under section 7 or black-listing him under section 8, the prescribed authority shall give notice to the dealer of the ground or grounds on which it is proposed to take action and hold an inquiry in the presence of the dealer giving him a reasonable opportunity of showing cause against it. Notice of removal and black-listing of a dealer.

CHAPTER III

REGISTRATION OF HOTELS

10. (1) Every person intending to operate a hotel in a tourist area shall, before operating the hotel, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner. Registration of hotels.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any person already operating a hotel in a tourist area on the date a notification under clause (q) of section 3, is issued, shall apply for registration within three months from the aforesaid date ;

(3) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of three months from the date of receipt of the application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

11. The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 12, direct the entry of the name and particulars of the hotel and the hotel-keeper to be entered in the register maintained for the purpose, and shall issue a certificate of registration to the hotel-keeper in the prescribed form. Certificate of registration of a hotel.

12. The prescribed authority may refuse registration of a hotel under this Act on any of the following grounds, namely :— Refusal to register a hotel.

- (a) if the hotel-keeper is convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him ;
- (b) if the hotel-keeper has been declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged ;
- (c) if the name of the hotel-keeper has been removed from the register on the grounds mentioned in clauses (c), (d), (e) or (g) of section 13 and three months have not elapsed since the date of such removal ;
- (d) if the premises do not conform to the prescribed standards ;
- (e) if the hotel-keeper does not hold a licence or certificate required to be held by him under any law for the time being in force ; and
- (f) if in the opinion of the prescribed authority, there is any sufficient ground, to be recorded in writing, for refusing registration :

Provided that no application for registration shall be refused unless the persons applying for registration has been allowed an opportunity of being heard.

Removal of
the name of
a hotel from
the register.

13. The prescribed authority may, by an order in writing, remove the name of a hotel from the register and cancel its certificate of registration on any of the following grounds, namely :—

- (a) if the hotel-keeper ceases to operate the hotel in the tourist area for which he is registered ;
- (b) if the hotel-keeper is convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him ;
- (c) if the hotel-keeper is declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged ;
- (d) if the hotel-keeper fails to comply with any of the provisions of this Act or rules framed thereunder ;
- (e) if the hotel-keeper fails to remove a lodger or wilfully keeps the lodger in a hotel, who becomes a nuisance for the inmates in an adjoining building ;
- (f) if any complaint of malpractice is received and proved against a hotel-keeper ;
- (g) if the hotel is black-listed under section 14; and
- (h) if the hotel-keeper provides accommodation in the hotel to local residents of the area in preference to the tourists visiting the area.

Black-list-
ing of hotels.

14. (1) The prescribed authority may, on proof of complaint of malpractice or for any other offence committed under this Act, for reasons to be recorded, black-list a hotel, after taking into consideration the nature of malpractice or gravity of the offence, for a period which may extend to six months.

(2) The particulars of a black-listed hotel shall be exhibited at conspicuous places in all tourist areas and notified to all travel, trade and other concerned organisations, foreign missions in India and Indian missions abroad.

(3) The action taken under sub-section (1) shall not protect such hotel, keepers from being prosecuted under the provisions of this Act.

(4) If the prescribed authority is satisfied that there are sufficient grounds for removal of a hotel from the black-list, it may, after recording the reasons, order its removal from such list and issue a fresh certificate of registration on payment of the prescribed fee and notify the same for the information of all concerned.

Notice of
removal and
black-listing
of a hotel.

15. Before removing the name of a hotel from the register under section 13 or black-listing it under section 14, the prescribed authority shall give notice to the hotel-keeper of the ground or grounds on which it is proposed to take action and hold an enquiry in the presence of the hotel-keeper giving him a reasonable opportunity of showing cause against it.

Fixation of

16. The prescribed authority may, in consultation with the committee to be constituted in the prescribed manner,—

- (a) fix the reasonable maximum rates and service charges, if any, commensurate with the standard of the hotel and quality of food, accommodation and service, which may be charged by the hotel-keeper during “season” and “off season” periods for board or lodge or for both from persons staying therein or from other customers :

Provided that the rates for lodging shall be fixed with reference to each room or specified accommodation and the number of the lodgers to be accommodated ;

- (b) fix the percentage of accommodation of daily and monthly lodgers in a hotel ;
- (c) fix the number of lodgers to be accommodated in each room or with in the specified accommodation in the hotel ;
- (d) fix fair rates separately for daily and monthly lodgers.

Explanation.—For the purposes of this chapter, a lodger who agrees to reserve accommodation in a hotel for a period of less than a month shall be deemed to be a daily lodger.

17. The prescribed authority may, from time to time, revise the fair rates, (the percentage of accommodation or the number of lodgers) fixed under section 16. Revision of fair rates.

18. Till such time the prescribed authority has not fixed fair rates, the percentage of accommodation and the number of lodgers, as required under section 16, the hotel-keeper shall fix and notify these to the prescribed authority by the 31st March each year and separate rates will be fixed for “season” and “off season” periods. Fixation of rates pending such fixation by the prescribed authority.

19. Where under section 16 or section 17 the prescribed authority has fixed or revised the fair rates, the percentage of accommodation or the number of lodgers, or even in case where the prescribed authority has not fixed rates, etc. , the hotel-keeper shall display a notice of the fair rates, the percentage of accommodation, the number of lodgers at a conspicuous place in the hotel and an agent of the hotel-keeper shall also keep a copy certified by the prescribed authority of such information on his person. Display of information.

(1) Notwithstanding any agreement to the contrary, no hotel-keeper shall charge any amount in excess of the fair rates fixed.

20. Any sum paid by the lodger in excess of the fair rate shall be recoverable by him at any time within one year from the date of payment from the hotel-keeper and may, without prejudice to any other remedy for recovery be adjustable by such lodger for an amount payable by him to the hotel. Charges recoverable in excess of fair rates.

21. No hotel-keeper shall evict or refuse board or any other service to a lodger so long as he pays or is ready and willing to pay the rate fixed and observes and implements the other conditions of his agreement in so far as they are consistent with the provisions of this Act: No ejectment to be made if fair rate paid.

Provided that where, under section 16 or section 17, the prescribed authority has fixed or revised the percentage of accommodation for daily and monthly lodgers respectively, the hotel-keeper may refuse accommodation to any daily or monthly lodger if the accommodation in respect of such class of lodgers is fully occupied.

22. Notwithstanding anything contained in this Act, a hotel-keeper shall be entitled to recover possession of the accommodation provided by him on When hotel-keeper may recover possession.

obtaining a certificate from the prescribed authority to the effect that—

- (a) the lodger has been guilty of conduct which constitutes a nuisance or an annoyance to any adjoining or neighbouring lodgers; or
- (b) the accommodation is reasonably and bona fide required by the owner of the hotel either for his own occupation or for any other cause which may be deemed satisfactory by the prescribed authority; or
- (c) the lodger staying on monthly basis is habitually irregular (or has been a defaulter for three months) in making payment of the charges for board, lodging or other service provided in the hotel; or
- (d) the lodger has failed to vacate the accommodation on termination of the period of the agreement in respect thereof :

Provided that before issuing a certificate under this clause, the prescribed authority would take into consideration the vacancies, if any in the accommodation for daily and monthly lodgers at that time ; or

- (e) the lodger has done any act which is inconsistent with the purpose for which the accommodation is provided to him or which is likely to effect adversely and substantially the hotel-keepers interest therein :

Provided that before issuing the certificate a reasonable opportunity will be given to the lodger to present his case.

Hotel-keeper to present detailed bills.

23. Every hotel-keeper shall present detailed bills to the person residing in the hotel and other customers and shall give receipt in acknowledgement of all payments.

When the hotel-keeper may honour confirmation of bookings at a particular rate.

24. If a hotel-keeper confirms a booking at a particular rate, it will, even if accommodation at higher rates alone is available at the time of arrival of the person for whom accommodation stands booked be honoured at the same rate.

Inspection with or without notice.

25. The prescribed authority or any other officer authorised by him to inspect hotel premises from time to time will be allowed free access with or without prior notice.

CHAPTER IV

TRAVEL AGENTS

Registration of travel agents, excursion agent or guide.

26. (1) No person shall carry on the business of a travel agent, excursion agent or guide in a tourist area unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.

(2) Every person intending to act as a travel agent, excursion agent or guide in a tourist area shall, before he commences to act as such, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), any person acting as a travel agent in a tourist area on the date a notification under clause (g) of section 3 is issued, shall apply for registration within three months from the aforesaid date.

(4) Every application made under this section shall be disposed of within a period of three months from the date of receipt of the application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

27. The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 28, direct the entry of the name and particulars of the travel agent, excursion agent or guide to be made in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate of registration to the travel agent, or excursion agent or guide as the case may be in the prescribed form.

Certificate of registration of travel agents etc.

28. The prescribed authority may refuse the registration of a travel agent, excursion agent or guide under this Act on any of the following grounds, namely:—

Refusal to register a travel agent, excursion agent or guide.

45 of 1860

- (a) if he does not possess any of the prescribed qualifications;
- (b) if he has been convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;
- (c) if he has been declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
- (d) if his name has been removed from the register on the ground mentioned in clauses (c), (d) or (e) of section 29 of this Act and 3 months have not elapsed since the date of such removal; and
- (e) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground, to be recorded in writing, for refusing registration :

Provided that no application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

29. The prescribed authority may, by an order in writing, remove the name of a travel agent, excursion agent or guide as, the case may be, from the register and cancel his certificate of registration on any of the following grounds, namely:—

Removal of the name of travel agents etc. from the register.

45 of 1860

- (a) if he ceases to act as a travel agent in a tourist area;
- (b) if he is convicted of any offence under chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;
- (c) if he is declared as an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
- (d) if any complaint of malpractice is received and proved against him; and
- (e) if he is black-listed by the prescribed authority.

30. (1) The prescribed authority may, on proof of any complaint of malpractice or for any other offence committed under this Act, for reasons to be recorded, black-list a travel agent after taking into consideration the nature of the malpractice or the gravity of offence, for such period as the prescribed authority may deem fit.

Black-listing of travel agents.

(2) The particulars of a travel agent black-listed shall be exhibited at conspicuous places and notified to all travel, trade and other concerned organisations, foreign missions in India and Indian missions abroad.

(3) The action taken under sub-section (1) shall not protect such travel agent from being prosecuted under the provisions of this Act.

(4) If the prescribed authority is satisfied that there are sufficient grounds for removal of a travel agent from the black-list it may, after recording the reasons, order his removal from such list and issue a fresh certificate of registration on payment of prescribed fee and notify the same for the information of all concerned.

Notice of removal and black-listing of travel agents.

31. Before removing the name of a travel agent from the register under section 29 or black-listing him under section 30, the prescribed authority shall give notice to the travel agent of the ground or grounds on which it is proposed to take action and hold an inquiry in the presence of that person, giving him a reasonable opportunity of showing cause against it.

Fixation of rates.

32. The prescribed authority may, by notification in the Official Gazette, fix fair rates which may be charged by a travel agent for the services rendered by him to a person engaging him as such.

Revision of fair rates.

33. The prescribed authority may, from time to time, revise the fair rates fixed under section 32.

When travel agent fixes and notifies the rates.

34. Till such time the prescribed authority has not fixed fair rates, the travel agent shall fix and notify these to the prescribed authority by 31st day of March, each year.

Display of information.

35. Where under section 32 or section 33, the prescribed authority has fixed or revised the fair rates or even in case the prescribed authority has not fixed rates, the travel agent shall display a notice, at a conspicuous place in his office, of the fair rates and such information as may be prescribed.

Charges paid in excess of fair rates.

36. (1) Notwithstanding any agreement to the contrary, no travel agent shall charge any amount in excess of the rates fixed.

(2) Any sum paid by a person in excess of the fair rate shall be recoverable by him at any time within one year from the date of payment from the travel agent and may, without prejudice to any other remedy for recovery, be adjustable by such person for any amount payable by him to the travel agent.

No refusal to render services.

37. No travel agent shall, without a reasonable excuse, refuse to make available his services to any person so long as he pays and is ready and willing to pay the rates fixed.

Travel agents to present detailed bills.

38. Every travel agent shall present detailed bills to the person availing his services and shall give receipts in acknowledgement of all payments received.

Travel agents not to demand tips, etc.

39. Travel agent is not to demand tips, gratuity, presents or commission other than as provided under this Act from any person engaging him or from any hotel-keeper in whose hotel such person resides or intends to reside.

CHAPTER V

APPEAL AND REVISION

40. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie from every order of the prescribed authority under this Act to the appellate authority to be appointed by the Government. Appeal.

(2) Every such appeal shall be preferred within ninety days from the date of communication of the order :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(3) The appellant shall have a right to be represented by a counsel or by a duly authorised agent and the prescribed authority may be represented by such officer or person as the prescribed authority may appoint.

(4) On receipt of any such appeal, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such enquiry as it deems proper, pass such order as it may deem fit, after recording the reasons therefor.

41. The revisional authority to be appointed by the Government may, either on its own motion or on an application made by an aggrieved party, call for the records of any case disposed of by the appellate authority, for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by the appellate authority and pass such order thereon as it may deem fit and such order shall be final: Revision.

Provided that no such record shall be called for after the expiry of three months from the date of communication of the order :

Provided further that no order under this section shall be made to the prejudice of a person unless he has had a reasonable opportunity of being heard either personally or through a counsel or by a duly authorised agent.

CHAPTER VI

OFFENCES AND PENALTIES

42. Any person carrying on business of a dealer, hotel-keeper or travel agent without a proper registration under this Act or in violation of any of the provisions of this Act shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both, and if the breach is a continuing one with a minimum fine of one hundred rupees per day and maximum of one thousand rupees per day depending upon the classification of the hotel, or the travel agency, as the case may be, made in the manner prescribed by the Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee constituted by the State Government from time to time. Penalty for default in registration.

Explanation.—A person who has made an application within the prescribed period and which is pending disposal shall not be a defaulter for the purposes of this section.

Penalty for false statement.

43. If any person required to make a statement under this Act wilfully makes a false statement or suppresses a material fact with an intention to mislead the prescribed authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both.

Certificate not to be assigned.

44. Any person who lends, transfers or assigns the certificate of registration issued under this Act, without the permission in writing of the prescribed authority, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

Certificate to be shown to persons on demand.

45. (1) Any person registered under this Act shall at all times, on demand, produce and show his certificate to any of the following persons, namely:—

- (a) the prescribed authority or any officer duly authorised by it in this behalf; and
- (b) any *bona fide* customer.

(2) Any person who refuses on demand to show his certificate to, or allow to be read by, any of the persons authorised to demand it, shall be punishable with fine not exceeding five hundred rupees.

Penalty for malpractice.

46. Any hotel-keeper or travel agent who commits a malpractice in a tourist area or contravenes any other provision of this Act for which no specific penalty has been provided, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

Obstructing lawful authorities.

47. If any person wilfully obstructs or offers any resistance to, or otherwise interferes with the discharge of the functions of the prescribed authority or any officer authorised by it exercising any power, or performing any duties conferred or imposed upon it or him by or in pursuance of this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to punishment with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both.

Power of the court to try cases summarily.

48. All offences under this Act may be tried in a summary way by a Chief Judicial Magistrate or an other Magistrate of the 1st Class specially authorised by the High Court and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply to such a trial:

Provided that when at the commencement of, or in the course of a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that it is, for any reasons, undesirable to try summarily, the Magistrate shall after hearing the parties record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

Institution of proceedings.

49. No prosecution shall be instituted against any person for any offence under this Act, except on a complaint made by the prescribed authority or the officer authorised by it in this behalf.

5 of 1908 50. The prescribed authority shall have all, the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while hearing an application under this Act, in respect of the following matters, namely:—

Power of prescribed authority to summon and enforce attendance of witnesses and other persons.

- (i) summoning and enforcing attendance of the complainant or the person against whom complaint is made under this Act and witnesses required in connection therewith;
- (ii) compelling the production of any document; and
- (iii) examining witnesses on oath;

and may summon and examine *suo moto* any person whose evidence appears to be material.

51. (1) The prescribed authority may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, a sum of money by way of composition of such offence and may out of the money so received compensate the person against whom the offence has been committed to the extent the prescribed authority deems reasonable.

Composition of offences.

(2) On the composition of offence, no further proceeding in respect thereof shall be taken against the accused and if any proceeding has already been instituted against him in a court, the composition shall have the effect of acquittal.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

52. Whenever a business for which a certificate of registration is held by a person devolves; by inheritance or otherwise, upon any other person or undergoes a change in respect of any particular entered in the registers under this Act, such person shall, within one month of the date of such devolution or change, notify in writing the fact to the prescribed authority.

Notification of changes.

(2) The prescribed authority shall make necessary changes in the register maintained for the purpose and in the certificate of registration.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the prescribed authority may remove from the register the name of the person in whose favour the certificate was issued and cancel the certificate of registration, if the successor is not eligible to be registered under this Act.

53. When a certificate of registration is cancelled under this Act, the person holding the certificate shall, within seven days from the date of service in a prescribed manner of the order of cancellation, return it to the prescribed authority.

Return of the certificate of registration.

54. If a certificate of registration issued under this Act is lost, damaged or destroyed, the prescribed authority shall, on an application made in that behalf by the person holding such certificate and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate certificate.

Duplicate certificate.

55. Every certificate of registration issued under this Act shall expire after a period of three years from the date on which it is issued or renewed, and on an application made to it and on payment of such fee as may be prescribed,

Renewal of certificate.

the prescribed authority, unless--

- (i) the certificate holder has ceased to be in business; or
- (ii) the certificate holder has incurred any disqualification for being registered under this Act; or
- (iii) the certificate holder's name has been removed from the register and the period for which his name has been removed has not expired; or
- (iv) the certificate holder has been black-listed and the order black-listing him has not been revoked; shall renew the certificate of registration for a further period of three years at a time.

Certificate of registration to be kept exhibited.

56. The certificate of registration shall be kept by the person holding it in a conspicuous place at the principal place of his business and if he has no principal place of business or acts otherwise than in any particular place, he shall keep it on his person.

Publication of list of persons removed from the register.

57. The prescribed authority shall, from time to time, publish in the Official Gazette and in such other manner as it deems fit, the names and addresses of the persons and of the hotels whose names have been removed from the register and have been refused registration under this Act.

Power to inspect.

58. The prescribed authority or any other person authorised by it in this behalf may, within the tourist area, inspect at all reasonable times, the premises in which a travel agent or a dealer carries on his business or any premises where a hotel is operated and required such dealer travel agent or hotel-keeper to produce any document kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder for inspection.

Proceedings before the prescribed authority to be judicial proceedings.

59. All proceedings before the prescribed authority under this Act shall be deemed to be judicial proceedings for the purpose of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

Idemnity.

60. No suit, prosecution or other legal proceeding whatsoever shall lie against the Government or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers of the Government to apply the Act to other persons.

61. The Government may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder shall, with such exceptions, adaptations or modifications as may be considered necessary, apply to persons doing the business in a tourist area of outdoor photography or of letting or plying for hire house-boats, dongas, bathing-boats, shikaras, automobile vehicles, tangas, dandis, pithus, ponies or to such other persons as may be specified in the notification and the prescribed authority may fix the rates to be charged for the services to be rendered.

Power to make rules.

62. (1) The Government may by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- (a) the maintenance of registers, books and forms by hotel-keepers, or travel agents, for conduct of business;
- (b) the form of application for registration and of certificate of registration;

- (c) the fee for registration;
- (d) the manner of giving notices under this Act;
- (e) manner of publication of the names and addresses of the persons removed from the register or to whom registration has been refused;
- (f) classification of hotels and travel agents;
- (g) qualifications for registration as travel agents and guides;
- (h) manner of publication of the names and addresses of the persons and the hotels removed from the register or to whom registration has been refused;
- (i) the manner in which a dealer, a hotel-keeper, or a travel agent shall be black-listed and the publication of names and addresses of such a dealer hotel-keeper or a travel agent;
- (j) the place where the prescribed authority shall hold inquiry under this Act; and
- (k) all matters expressly required to be prescribed under this Act.

(3) All rules made under this section shall be subject to condition of previous publication.

63. The Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 is hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that anything done or any action taken (including any notification issued, certificate or permission granted, or proceedings commenced or continued) under the provisions of the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Tourism has acquired a new dimension and is recognised as one of the major industries with invisible export. A large number of hotels, travel agents, photographers etc. have come up. The existing enactment on the subject i.e. the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 has been found deficient in tackling the problems connected with the tourist trade in the State. There is immediate need to recast the existing provisions so that the tourist agencies which indulge in malpractices like cheating, toutting, impersonation, charging higher prices and are not providing accommodation to tourists or providing accommodation on daily rent to persons other than *bona fide* tourists, may be effectively dealt with. There is no provision in the present Act for black-listing dealers, hotels and travel agents etc. and for renewal of certificates. Apart from this the penalties prescribed are too meagre and require enhancement in the context of the present day circumstances.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA:
The April 4, 1988.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-Charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in this Bill when enacted are likely to yield an approximate recurring income amounting to Rs. 5.50 lacs per annum as fees chargeable for registration to be made under clauses 4, 10 and 26 and from the court fees and penalties for offences committed under any of the provisions of the Bill. Additional expenditure to the tune of Rs. 3.50 lacs (out of which 1 lac rupees will be non-recurring expenditure and rupees 2.50 lacs shall be recurring expenditure) is likely to be involved in the implementation of various provisions of this Bill as the existing machinery will have to be augmented.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 62 empowers the Government to make rules in respect of matters mentioned therein. The rules so made are subject to the condition of previous publication and are to be laid in the Legislative Assembly. The proposed delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Tourism Department File No. 5-3/86-TSM(Sectt.)]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tourist Trade Bill, 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

